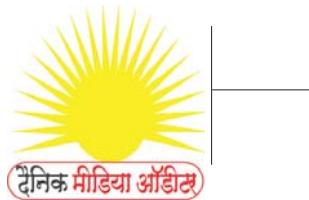


सतना
30 जनवरी 2025
गुरुवार



दैनिक

मीडिया ऑडिटर



सतना, रीवा से एक साथ प्रकाशित

@ पेज 7

महाकुंभ मेले में भगदड़ से 30 की मौत, 60 घायल



पीड़ित परिवारों को 25 लाख की
मदद का ऐलान

बिहार (एजेंसी)। महाकुंभ मेले में बुधवार तक संगम नोज पर मची भगदड़ की वजह से अब तक तीस लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे पर बुधवार शाम मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भासुक हो गए। उन्होंने बताया कि उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिजनों के साथ घर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ज्ञाना प्रेसर प्रशासन में होने के कारण मार्ग चाक थे। प्रशासन उन्हें खुलासा में लगा रहा।

सीएम योगी ने बताया कि सरकार ने घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने सप्तसौयी न्यायिक जांच कमेटी इस मामले को देखेगी। कमेटी में जस्टिस हर्ष कुमार के अलावा पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड हस्ट वीके सिंह को शामिल किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस भी इस हादसे की जांच करेगी। सीएम योगी की तरफ से पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपये की मदद का ऐलान किया गया है।

इससे पहले महाकुंभ मेले के छठवत् वैभव कृष्ण ने बताया कि महाकुंभ में रात 1 से 2 बजे

के बीच हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इनमें से 25 की पहचान की जा चुकी है। डीआइजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने बताया कि हादसे के बाद 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।

महाकुंभ मेले में कैसे मची भगदड़? - डीआइजी कुंभ मेला वैभव कृष्ण ने बताया कि मौती अमावस्या स्नान के समय ब्रह्म मुहूर्त से पहले रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़े के रास्ते से जगह घायल श्रद्धालुओं को उनके रिसेंटर ले गए हैं। 36 घायलों का स्थानीय मंडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन ने हैट्प्लाइन नंबर 1920 जारी किया है।

महाराष्ट्र के मंत्री ने बोर्ड एजाम सेंटर्स पर इसे बैन करने की उठाई मांग

हिंजाब और बुर्का अपने घर पर पहनें,

महाराष्ट्र के मंत्री ने बोर्ड एजाम सेंटर्स पर इसे बैन करने की उठाई मांग

महाकुंभ में तीन शंकराचार्यों ने किया अमृत स्नान



प्रयागराज (एजेंसी)। मौती अमावस्या पर सबसे पहले तीन शंकराचार्यों ने अमृत स्नान किया। इसके बाद साधु-संतों ने छोटे-छोटे गुप में अपने इष्टदेव के साथ सांकेतिक रूप से संगम स्नान किया।

जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशनंद गिरि महाराज रथ पर निकले। नागा साधुओं ने तलवार लहाई। जयकरे लगाते हुए संगम घाट पहुंचे। निरजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरि महाराज ने संगम में डुबकी लगाई। हेलिकॉप्टर से संतों और श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई।

इससे पहले बुधवार तड़के अखाड़ों के साधु-संतों और स्नान के लिए निकले थे। इस बीच, भगदड़ के बाद संगम पर हालात बेकबू हो गए।



गडबड़ी की संभावना बढ़ सकती है। बुर्के और हिंजाब पर पारंबंदी इसलिए लगानी चाहिए इसकी आड़ में हिंदुओं के लिए जब सामान नियम हैं तो वह नियम मुस्लिम छात्राओं के लिए भी होने चाहिए। राणे ने आगे कहा कि आगामी बोर्ड एजाम में छात्राओं को बुर्का पहनकर परीक्षा देने से रोका जाए।

क्या कहा है नितेश राणे ने?

नितेश राणे ने अपने खत में यह अनुरोध किया है कि 10वीं-12वीं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं में सेंटर पर किसी भी छात्रा को बुर्का पहनकर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे परीक्षा में बुर्के और हिंजाब पर पारंबंदी इसलिए लगानी चाहिए। राणे ने आगे कहा कि आगामी बोर्ड एजाम के अंतर्गत नहीं जाएं जानी चाहिए।

बुर्के की आड़ में हो सकती है। नितेश राणे ने कहा है कि स्कूलों में हिंदुओं के लिए जब सामान नियम हैं तो वह नियम मुस्लिम छात्राओं के लिए भी होने चाहिए। राणे ने आगे कहा कि आगामी बोर्ड एजाम में छात्राओं को बुर्का पहनकर परीक्षा देने से रोका जाए।

बुर्के और हिंजाब पर पारंबंदी इसलिए लगानी चाहिए इसकी आड़ में हिंदुओं के लिए जब सामान नियम हैं तो वह नियम मुस्लिम छात्राओं के लिए भी होने चाहिए। राणे ने आगे कहा कि आगामी बोर्ड एजाम में छात्राओं को बुर्का पहनकर परीक्षा देने से रोका जाए।

बुर्के की आड़ में हो सकती है। नितेश राणे ने कहा है कि इस मामले में कठोर कदम: नितेश राणे ने कहा है कि

मोदी ने भरे मंच पर बीजेपी कैडिट के तीन बार छुए पैर



नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों का प्रचार अध्यायन चाही रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने करतार नगर विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवारी घोषित किया है। करतार नगर की संकल्प रैली में नेता भी प्रतीक्षित है।

रैली के दौरान एक ऐसा भी नजारा सामने आया जब पीएम मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार के एक नहीं बल्कि तीन बार पैर छुए। इसका बीड़ियों अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पटपड़ांज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र सिंह नेता को अपना उम्मीदवारी घोषित किया है। करतार नगर की संकल्प रैली में नेता भी मौजूद थे। जब मंच पर उनका नाम अनादेश किया गया तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके पैर छुए। इसके तुरंत बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्र नेता के एक नहीं बल्कि तीन बार पैर छुए। इस दौरान मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के अव्यैक्टिक भी काफी अहसंज हो गए।

रैली में नेता भी मौजूद थे। जब मंच पर उनका नाम अनादेश किया गया तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके पैर छुए। इसके तुरंत बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्र नेता के एक नहीं बल्कि तीन बार पैर छुए। इस दौरान मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के अव्यैक्टिक भी काफी अहसंज हो गए।

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर राजनीति गर्म है। बुधवार सुबह दिल्ली में रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में हमारे सारे जगह, जैसे, जस्टिस, सम्मानित सदस्य पीते हैं।

महिला कांस्टेबल ने बिना किसी डर के तस्करों को तरफ दौड़े हुए बदले हुए देखा। तस्करों के अवैधतिक प्रयास को देखकर महिला कांस्टेबल ने तुरंत अपने साथियों को

सतर्क किया और तस्करों को चेतावनी दी। लेकिन तस्कर समझ में नहीं आयी। तस्करों ने बदले हुए देखकर महिला कांस्टेबल के तरफ दौड़े हुए देखा। तस्करों की ओर से बदले हुए देखकर महिला कांस्टेबल ने तुरंत अपने साथियों को जहर वाले बयान पर राजनीति गर्म है। बुधवार सुबह दिल्ली में रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में हमारे सारे जगह, जैसे, जस्टिस, सम्मानित सदस्य पीते हैं।

महिला कांस्टेबल ने बिना किसी डर के तस्करों को तरफ दौड़े हुए देखा। तस्करों की ओर से बदले हुए देखकर महिला कांस्टेबल ने तुरंत अपने साथियों को जहर वाले बयान पर राजनीति गर्म है। बुधवार सुबह दिल्ली में रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में हमारे सारे जगह, जैसे, जस्टिस, सम्मानित सदस्य पीते हैं।

महिला कांस्टेबल ने बिना किसी डर के तस्करों को तरफ दौड़े हुए देखा। तस्करों की ओर से बदले हुए देखकर महिला कांस्टेबल ने तुरंत अपने साथियों को जहर वाले बयान पर राजनीति गर्म है। बुधवार सुबह दिल्ली में रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में हमारे सारे जगह, जैसे, जस्टिस, सम्मानित सदस्य पीते हैं।

महिला कांस्टेबल ने बिना किसी डर के तस्करों को तरफ दौड़े हुए देखा। तस्करों की ओर से बदले हुए देखकर महिला कांस्टेबल ने तुरंत अपने साथियों को जहर वाले बयान पर राजनीति गर्म है। बुधवार सुबह दिल्ली में रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा का भ

संपादकीय

दिल्ली में इस बार जनता के लिए घोषणापत्र
नहीं, लॉटरी पेश कर रहे हैं राजनीतिक दल

इस समय दिल्ली में सेल चल रही है। वैसे अक्सर सेल में 50 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा की छूट दी जाती है लेकिन दिल्ली में चुनावी मौसम में चल रही सेल में 100 प्रतिशत की छूट है। यानि सब कुछ मुफ्त। सब कुछ मुफ्त देने से सरकारी खजाने को कितना नुकसान होगा इसकी परवाह किसी को नहीं है क्योंकि हर पार्टी विधानसभा में अपनी सीटें किसी भी कीमत पर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सब कुछ मुफ्त देने से दिल्ली में महंगाई का आलम क्या होगा यह सोचे बिना राजनीतिक दल गारंटियों पर गारंटियों की घोषणा किये जा रहे हैं। सब कुछ मुफ्त देने से लोगों का सशक्तिकरण होने की बजाय उनके निठले बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं लेकिन फिर भी सब कुछ फ्री देने की होड़ में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से आगे निकली जा रही हैं। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा है उसके बावजूद यहां के लोगों को फ्री में सुविधाएं हासिल करने की आदत लगा दी गयी है। सरकारी खजाने को लूटो और लुटाओ की नीति के चलते दिल्ली का राजस्व नुकसान हुआ, भ्रष्टाचार के अवसर बढ़े, दिल्ली का बजट घाटा बढ़ा लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इसीलिए यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली की सत्ता पाने को आतुर पार्टियां एक दो नहीं बल्कि अपने आधा आधा दर्जन घोषणापत्र जारी कर रही हैं। पहले चुनावों में किसी राजनीतिक दल का घोषणापत्र उसकी नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं से निजात दिलाने की रूपरेखा प्रस्तुत करता था लेकिन आज पार्टियों का घोषणापत्र उनकी सत्ता लोलुपता को प्रदर्शित कर रहा है। देखा जाये तो यह घोषणापत्र नहीं बल्कि लॉटरी पेश करने जैसा है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ही बात कर लें तो बिजली और पानी फ्री देने की राजनीति शरू करने वाली इस पार्टी ने पैकेज के रूप में बिजली और पानी के साथ मौत भी फ्री ही रखी है क्योंकि इस पार्टी के राज में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते हर उम्र के लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हो गयी हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जन लोकपाल लाने का वादा किया था लेकिन भ्रष्टाचार के नये रिकॉर्ड बना दिये, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने का ढोल पीटा जबकि असल में एक बोतल पर दूसरी बोतल फ्री देकर दारू क्रांति लाई गयी। आम आदमी पार्टी ने सादगी और शुचिता की बात की थी लेकिन उसके नेता शीश महल में रहे और सुरक्षा का बड़ा अमला तथा अन्य सुख सुविधाओं को भाँगते रहे। अब “केजरीवाल की गारंटी” शीर्षक से पार्टी का जो घोषणापत्र जारी किया गया है वह भी खजाने को लुटाने का छलावा दिखा कर मतदाताओं के मत लूटने का प्रयास लगता है। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के घोषणापत्र में 15 गारंटी का जिक्र है, जिसमें केजरीवाल ने अपनी पहली गारंटी के रूप में दिल्ली के निवासियों के लिए रोजगार सृजन के “ठोस” कदम का वादा किया है। बहरहाल, देखा जाये तो मुफ्त सुविधाएं केवल अल्पकालिक राहत प्रदान करती हैं। जबकि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल सिखाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही मतदाताओं को इन लाभों की कीमत के बारे में पता होना चाहिए जो अंततः जनता की जेब से ही आती है। यहां तक कि निर्धनतम व्यक्ति भी अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स दे रहा है।

मध्यमवर्गीय परिवार ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों (दोपहिया वाहन, चारपहिया वाहन, फ़िज, एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों एवं नए फ्लेट्स एवं भवनों आदि) को खरीदने पर अपनी आय के अधिकतम भाग का उपयोग करता है। इससे अर्थिक चक्र में तीव्रता आती है और इन उत्पादों की बाजार में मांग के बढ़ने के चलते इनके उत्पादन को विभिन्न कम्पनियों द्वारा बढ़ाया जाता है, इससे इन कम्पनियों की आय एवं लाभप्रदता में बढ़ि होती है एवं देश में गोजागां के ना अत्यधिक निर्मित होते हैं।

भारत में पिछले कुछ समय से मध्यमवर्गीय परिवारों की व्यय करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है अतः दिनांक 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्र सरकार के बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विशेष रूप से आय कर में छूट की घोषणा करेंगी। देश के कई अर्थशास्त्रियों का तो यह भी कहना है कि न केवल आय कर में बल्कि कारपोरेट कर में भी कमी की घोषणा की जानी

चाहिए। इनफोसिस के संस्थापक सदस्यों में शामिल श्री मोहनदास पई का तो कहना है कि 15 लाख से अधिक की आय पर लागू 30 प्रतिशत की आय कर की दर को अब 18 लाख से अधिक की आय पर लागू करना चाहिए। आय कर मुक्त आय की सीमा को वर्तमान में लागू 7.75 लाख रुपए की राशि से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर देना चाहिए। आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत किए जाने निवेश की सीमा को भी 1.50 लाख रुपए की राशि से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर देना चाहिए। मकान निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर अदा किए जाने वाले ब्याज पर

गांवों की खुशहाली मापने के लिए बनाएं नए मानदंड

उमेश चतुर्वेदी

दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले अपने देश की पहचान उसके गांव रहे हैं। देश सिर्फ ग्रामीण संस्कृति और कृषि व्यवस्था के लिए ही नहीं, सहकार और शिल्पकारी के लिए भी वैश्विक पहचान रखते रहे हैं। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले दौर में भी भारतीय कृषि और आर्थिकी के आधार गांव ही रहे। यह बात और है कि अंग्रेजी शासन के दौरान से भारतीय गांवों का पतन शुरू हुआ। इसके बाद भारतीय गांव गरीबी और मजबूरी के पर्याय माने जाने लगे। लेकिन घरेलू उपयोग और खर्च के ताजा सर्वेक्षण की रिपोर्ट बता सकी है कि गांवों की आर्थिक कट्टीर बदलने लगी है।



भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से घरेलू उपयोग और खर्च के लिए कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार शहरी और ग्रामीण इलाकों में घरेलू खर्च का जो पहले अंतर रहता था, वह लगातार घटता चला गया है। अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, ग्रामीण और शहरी भारत में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च 4,122 रुपये और 6,996 रुपये हो गया है। जबकि पहले यानी 2022 से 2023 के बीच यह खर्च क्रमशः 3,773 रुपये और 6,459 रुपये थाय़ यानी शहरी और ग्रामीण भारत की प्रति व्यक्ति खर्च दर में बढ़ा अंतर था। मोटे तौर पर यह आंकड़ा बता रहा है कि हाल के दिनों में ग्रामीण इलाकों में आर्थिक समृद्धि पहले की तुलना में बढ़ी और उस लिहाज से खर्च भी बढ़ा है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, जबकि 32 प्रतिशत आबादी शहरों में है। स्वाधीन भारत में विशेषकर उदारीकरण के बाद जिस तरह का विकास मॉडल हमने अपनाया, उसमें शहरी विकास पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, ग्रामीण विकास या तो रस्मी रहा या फिर उस पर फोकस शहरों की तुलना में कम रहा। शहरों की ओर रोजगार और जीवन सुविधाएं केंद्रित होती चली गईं। शिक्षा के भी बेहतर अवसर गांवों की तुलना में शहरों की ओर

2011 का जनगणना के अनुसार भारत का 68 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, जबकि 32 प्रतिशत आबादी शहरों में है। स्वाधीन भारत में विशेषकर उदारीकरण के बाद जिस तरह का विकास मॉडल हमने अपनाया, उसमें शहरी विकास पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, ग्रामीण विकास या तो रस्सी रहा या फिर उस पर फोकस शहरों की तुलना में कम रहा। शहरों की ओर रोजगार और जीवन सुविधाएं केंद्रित होती चली गईं। शिक्षा के भी बेहतर अवसर गांवों की तुलना में शहरों की ओर

लिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे ज्यादा और शिक्षा के लिए हुआ। फिर जिन परिवारोंने अपनी हैसियत और उसे मुफीद पाए जाने वाले शहरों की ओर रहने की यात्रा। यही बजह है कि शहरी और ग्रामीण ननुपात आबादी के समय था, वह आज बदल गया। केंद्र के वक्त तकरीबन 80 फीसद से ज्यादा लोग अनुमान है कि वह घटते-घटते अब साठ द के बीच आ गई है। रिकॉर्ड पर ग्रामीण गांव बड़ा हिस्सा भले ही गांवों में बसता हो, यह है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में शिक्षा के लिए कभी शौकिया तो कभी न को मजबूर है। इसलिए रिकॉर्ड की तुलना में आबादी अब और भी कम हो चुकी है। के इस नए आंकड़े को देखते वक्त हमें इस न देना होगा। बहरहाल हमें यह भी ध्यान देना इलाकों में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का या पारिवारिक खर्च में कमी आई है। इसकी सरकार की ओर से तमाम तरह की योजनाएं कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं। मुफ्त खाद्यान्न ई अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के

जरिये मुफ्त में मिल रही चीजों की कीमतों को ध्यान में रखें तो घरेलू खर्च के ये आंकड़े ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 4,247 रुपये और 7,078 रुपये हो जाते हैं। मौजूदा कीमतों के संदर्भ में देखें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खर्च पर औसत आठ और नौ प्रतिशत की बढ़ोतारी हुई है। साल 2011-12 में शहरी और खपत खर्च के बीच 84 प्रतिशत का अंतर था, जो 2022-23 में घटकर 71 प्रतिशत हो गया। जो अब 70 फीसद ही रह गया है। इन आंकड़ों से ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खुशहाली की तसवीर सामने आती है। दिलचस्प यह है कि इस आंकड़े में खाने-पीने के अलावा की चीजों पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह खर्च 60 और 53 प्रतिशत रहा। इसका मतलब साफ है कि अब ग्रामीण इलाकों में भी वाहन, कपड़े, बिस्तर, जूते, मनोरंजन एवं टिकाऊ आदि सामानों पर खर्च बढ़ा है। इससे साफ है कि उपभोक्तावाद ने ग्रामीण इलाकों पर भी जोरदार दस्तक दी है। वैसे ऑनलाइन स्टोर से गांवों में खरीददारी बढ़ी है और उनके डिलीवरी एजेंटों की बाइकें अब ग्रामीण इलाकों का भी खूब चक्र लगा रही हैं।

पिछले साल मई में रिजर्व बैंक ने भी ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खपत खर्च को लेकर ऐसे ही आंकड़े जारी किए थे। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी रहेगी और देश की जीडीपी दर में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकती है। लेकिन रिजर्व बैंक ने इसी रिपोर्ट में ग्रामीण इलाकों में बढ़ते कर्ज को लेकर भी रिपोर्ट जारी की थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कर्ज को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके मुताबिक, कर्ज लेने में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कहीं ज्यादा आगे हैं। गांवों में प्रति एक लाख लोगों में 18,714 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने कोई न कोई कर्ज ले रखा है, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 17,442 प्रति लाख ही है। साफ है कि उपभोक्तावाद ग्रामीण संस्कृति को बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। कर्ज कभी गांवों के लोगों के लिए सिरदर्द होते थे, इसलिए वहां बचत केंद्रित आर्थिकी पर जोर था। लेकिन अब इसमें गिरावट आई है। इसका मतलब साफ है कि गांवों में खर्च भले ही बढ़ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि गांवों की तसवीर अभी कम से कम वैसी नहीं हो पाई है, जिस स्तर पर शहरी तसवीर है।

गांवों का समुद्र होना जरूरी है। हाल के दिनों में जनसंख्या को बढ़ाने और न बढ़ाने को लेकर सियासी तौर पर अपने-अपने तर्क दिए जा रहे हैं। इन तर्कों के अपने आधार हो सकते हैं। लेकिन इससे शायद ही कोई इनकार करेगा कि भारत के शहरों की सांस अगर फूल रही है तो इसकी बड़ी वजह उनकी ओर बेतहाशा हो रहा पलायन और उस बड़ी जनसंख्या के लिए इस्तेमाल हो रहे उपभोक्ता वस्तुओं का बड़ा योगदान है। भारत में आबादी बढ़ाने की जगह आबादी के समन्वित और संतुलित वितरण की जरूरत ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में आबादी को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। ग्रामीण आबादी को बुनियादी शिक्षा और रोजगार गांवों या उसके आसपास ही उपलब्ध कराने की नीतियों पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर आबादी को संतुलित किया जा सकेगा। तब गांव आबादी विहीन नहीं होंगे और शहरों पर आबादी का असंतुलित बोझ नहीं बढ़ेगा।

गांवों में हो रही खपत और खर्च को लेकर आ रहे आंकड़ों का पहला असर यही होना चाहिए कि गांवों में आबादी रुके। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण इलाके में बढ़ते खर्च से अब्वल तो गांवों में रोजगार के साधन बढ़ने चाहिए। लेकिन इस दिशा में ठोस बदलाव होते नजर

बेशक आज आजादी के बाद के दौर की तरह के बदहाल गांव नहीं हैं। बेशक शहरों जितना उसे बिजली नहीं मिलती, लेकिन पहले की तुलना में अब गांवों को भी बिजली ज्यादा मिल रही है। गांवों में भी उपभोक्ता वस्तुएं पहुंची हैं। इससे बेशक पारंपरिक संस्कृति चोट भले ही पहुंची हो। यह भी सच है कि ग्रामीण विकास और दूसरी कल्याण योजनाओं के जरिए गांवों में केंद्रीय और राज्य सरकारों की ओर से पैसा जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा जमीनी स्तर पर खर्च होने की बजाय नौकरशाही और राजनीतिक श्रिंथत के रूप में शहरी इलाकों में ही रुक रहा है और वहीं निवेशित हो रहा है। इस लिहाज से देखें तो ग्रामीण इलाके में जैसी समृद्धि दिखनी चाहिए, कम से कम जमीनी स्तर पर वैसी समृद्धि नहीं है। गांवों का जैसा रूप होना चाहिए, वैसा नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट से मिल सकती हैं कई सौगातें



प्रदान की जाने वाली आयकर छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाना

लाख रुपए से ज्याकर 3 लाख रुपए कीमत जाना
चाहिए।

फरवरी 2025 माह में ही भारतीय रिञ्जर्ब बैंक
द्वारा मोनेटरी पोलिसी की घोषणा भी होने जा रही
है। भारतीय रिञ्जर्ब बैंक से अब यह अपेक्षा की जा
रही है कि वे रेपो दर में कम से कम 25 अथवा 50
आधार बिंदुओं की कमी तो अवश्य करेंगे। क्योंकि,
पिछले लगातार लगभग 24 माह तक रेपो दर में

कोई भी परिवर्तन नहीं करने के चलते मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा मकान निर्माण एवं चार पहिया वाहन आदि खरीदने हेतु बैंकों से लिए गए ऋण की किश की राशि का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है। बैंक से लिए गए इस प्रकार के ऋणों एवं माइट्रोफाइनेंस की किशतों की अदायगी में चूक व घटनाएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मुख्यमानी की दर खाद्य पदार्थों (फलों एवं संविष्ट आदि) के कुछ महंगे होने के चलते ही उच्च स्तर

मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के लाभार्थियों के हितलाभ दो दिवस में वितरित करें

कलेक्टर ने टीएल की बैठक में दिये निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। कलेक्टर मैरें रानी बाटड ने मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के दोरान ग्रामीण और नागरिक क्षेत्र में आयोजित शिविरों में पावर हितग्राहियों के स्वीकृत हितलाभ अगले दो दिवस के भीतर वितरण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कहा कि 50 दिवस से ऊपर और चालू माह के शिक्षकों का अगले दो तीन दिन में संतुष्टिकरण रूप से निराकरण करायें। बुधवार का कलेक्टरेट समाजिक मैहर में सम्पन्न समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में अपर कलेक्टर शेलेन्ड्र सिंह, एसडीएम डॉ. आरती सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह, कार्यपालन यंत्री लोकनियम बीआर सिंह, उप संचालक समाजिक न्याय सौरभ सिंह, एसडीएम डॉ. पर्सद यशपाल मेहरा, सीईआर जनप्रतीक बागरी, ओपी अस्थाना, एमएल प्रजापाता, डीपीसी विष्णु त्रिपाठी



सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित हैं।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत आयोजित शिविरों और हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के स्वीकृत हितलाभ की समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि मैहर जैसे छोटे जिले में 7706 शिक्षकों का निराकरण स्वयं किए जाने की स्थिति में उचित कारण के प्रतिवेदन के साथ फेरसी कलेज कराये। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कुल लिखित 7706 शिक्षकों में जारी रखी गयी वात है। इनमें से 4474 शिक्षकों ने अपर कार्यक्रम के प्रतिक्रिया देखे हैं। सभी अधिकारी अपने विभाग की सीएम हेल्पलाइन को स्वतः देखे और समय पर निराकृत कराये।

उन्होंने कहा कि कोई भी शिक्षक न अट-एटेंड नहीं रहनी चाहिए। इसी प्रकार शिक्षकों की 140 सूचना प्रोटोकॉल की बैठक में कोई भी विवादपूर्ण जबाब दर्ज नहीं कराये। नियमानुसार शिक्षकों के कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में उचित कारण के प्रतिवेदन के साथ फेरसी कलेज कराये। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कुल लिखित 7706 शिक्षकों में जारी रखी गयी वात है। इनमें से 50 प्रतिशत शिक्षकों ने अपनी सूचना अनुपीक्षित रखने पर नागरिकता दर्ज करायी है। सभी अधिकारी अपने विभाग की सीएम हेल्पलाइन को स्वतः देखे और समय पर निराकृत कराये।

आकारी 24, स्कूल शिक्षा 65, सूचना प्रोटोकॉल की 140 सूचना प्रोटोकॉल सामिल हैं। कलेक्टर ने कहा कि फेरसी कलेज केनल पुरानी शिक्षावाही की जा सकती। लिखित शिक्षावाही का निराकरण स्वयं जिला अधिकारी देखें तो 50 प्रतिशत शिक्षकों ने अपनी सूचना अनुपीक्षित रखने पर नागरिकता दर्ज करायी है। कलेक्टर ने कहा कि परिवार मरमरी केन्द्र में 16 प्रकार भजे गए हैं। इन प्रकारों में कोई गई करने के लिए एक वाइकरी जारी रखी गई है। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय विभागों को भूमि आवंशक न के मामलों में चाही जाने वाली विभागीय अनपत्ति एनओसी समय पर भरें। इसी प्रकार सीएम मनिट प्रधारी मंत्री, आयोग एवं शासन से प्राप्त पत्रों के जलवायी के विगत कई बैठकों में उपस्थित नहीं रहने पर

सुनिश्चित करें। उन्होंने जनसुनवाई जारी करने के निर्देश दिये। समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में विनाशक विवेदन भी शीघ्र भेजने के निर्देश दिये।

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा में कोई परिसर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर अधिकारी संघर्ष लाइन थाने पहुंचे। जहाँ उन्होंने पुलिस पर ही आरोप लगा डाले। उधर पुलिस ने भी पूरे मामले में सफाई दी।

जो अब तक नहीं मिल पाई। अगर जल्द इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हम उग्र आदोलन भी करेंगे। फिलहाल आज हमें थाने का घेराव किया गया है।

पूरे मामले में सिविल लाइन थाना प्रधारी कमलेश साह ने बताया कि अधिकारी संघर्ष के लिए थाने में पहुंचे थे। बाइक चोरी के मामले पंजीयन करने के बिंदेचाना में लिया गया है। जल्द आरोपी को गिरफतार कर लेंगे।

न्यायालय परिसर की पार्किंग में सीधीटीकी कैमरे लगाने का सुझाव भी दिया जाएगा। ताकि पुलिस को मदद मिल सके। कोई भी गोपी आदमी बड़ी मुश्किल से एक बाइक खरीद पाता है। पुलिस बड़ी में नागरिकों के बाद अधिकारीओं ने आए दिन चोरी की घटना होने का आरोप लगाया। उधर पुलिस ने तकाल मामले में एकआईआर दर्ज कराया। कामरा को जिला शिक्षा अधिकारी एवं शासन से प्राप्त पत्रों के जानकारी के साथ उपस्थित होगे।

अधिकारी संघर्ष के लिए उपायक्षम तथा उपरोक्त सिंह ने बताया कि अधिकारी ओंगरी के बाइकरी ने एक बाइक खरीद पाता है। पुलिस बड़ी में नागरिकों के बाद चोरों की घटना दोपहर तक रही है। 23 तारीख को अधिकारी ओपी त्रिपाठी की गाड़ी चोरी हो गई जानकारी के साथ होगी।

कार से 1140 सीसी कफ सिरप जब्त एक नाबालिंग सहित चार गिरफतार, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में थे आरोपी



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा जिले में पुलिस ने संधन वाहन के लिए अधियान के दोरान अनेक बाइकरों को गिरफतार किया। जिला शान समान निलामी नामक बाइकरों द्वारा एक गिरफतारी की गई है।

चार आरोपी गिरफतार: पुलिस ने कमल नयन सिंह रुफ नमन ठाकुर (19), गुलप पटेल (24), विकास सिंह (18) और एक नाबालिंग को गिरफतार किया गया है। इसमें दो आरोपी त्रिपाठी के बाइकरों में से एक गिरफतार किया गया है।

एसपी विवेद के लिए उत्तर प्रदेश के लिए उपरोक्त सिंह ने बताया कि हिरासत के लिए उत्तर प्रदेश के लिए युवकों द्वारा एक गिरफतारी की गई है। युवकों द्वारा एक गिरफतारी की गई है। युवकों द्वारा एक गिरफतारी की गई है। युवकों द्वारा एक गिरफतारी की गई है।

मद्य निषेध संकल्प दिवस का आयोजन आज

मीडिया ऑडीटर, रीवा/सतना (निप्र)। जिले में महान्यांत्रिक अधियान के दोरान अनेक बाइकरों को गिरफतार किया गया है।

समाज में बढ़ते हुए मद्यालय तथा नशीली दवा, माटक, अधीकारी, शासकीय स्थानों पर व्यापक विवरण के लिए उपरोक्त सिंह ने बताया कि अधिकारी ने एक गिरफतारी की गई है। युवकों द्वारा एक गिरफतारी की गई है। युवकों द्वारा एक गिरफतारी की गई है। युवकों द्वारा एक गिरफतारी की गई है।

कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक सतना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना, अधिकारी ने कलेक्टर के लिए उपरोक्त सिंह को गिरफतार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कुंभ तीर्थ यात्रियों की समुचित व्यवस्था के लिए रीवा प्रशासन की प्रशंसा की

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. एमपीएच.आई.एन. 2021/81683 की सुनिश्चित कराई। मध्यप्रदेश उत्तरांचल की स्वीकृत योजनाओं में बोर्ड और बोर्डर अधिकारी ने एक गिरफतारी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कुंभ तीर्थ यात्रियों की समुचित व्यवस्था के लिए रीवा प्रशासन की प्रशंसा की। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक गिरफतारी की गई है।

उन्होंने कहा कि उत्तरांचल की समुचित व्यवस्था के लिए रीवा प्रशासन की प्रशंसा की गई है। युवकों द्वारा एक गिरफतारी की गई है।

हमारे प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने मोंके पर मौजूद रहने तक की गिरफतारी की गई है।

किसानों की समृद्धि के लिये बढ़ाई जा रही है कृषि उत्पादकता

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि और खुशहाली राज्य समाज की आवश्यकता विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी ने एक बड़ी उपलब्धि की दी। जिला कलेक्टर एवं संचालक समाजिक न्याय सौरभ सिंह, एसडीएम डॉ. आरती सिंह, आजीविका और उत्तरांचल की आयोजित विविध कार्यक्रमों के लिए उपलब्धि की दी।

प्रधानमंत्री प्रसाद बीमा योजना के अंतर्गत नागरिकों को विविध कार्यक्रमों के लिए उपलब्धि की दी। जिला कलेक्टर एवं संचालक समाजिक न्याय सौरभ सिंह, एसडीएम डॉ. आरती सिंह, आजीविका और उत्तरांचल की आयोजित विविध कार्यक्रमों के लिए उपलब्धि की दी।

प्रधानमंत्री प्रसाद बीमा योजना के अंतर्गत नागरिकों को विविध कार्यक्रमों के लिए उपलब्धि की दी। जिला कलेक्टर एवं संचालक समाजिक न्याय सौरभ सिंह, एसडीएम डॉ. आरती सिंह, आजीविका और उत्तरांचल की आयोजित विविध कार्यक्रमों के लिए उपलब्धि की दी।

प्रधानमंत्री प्रसाद बीमा योजना के अंतर्गत नागरिकों को विविध कार्यक्रमों के लिए उपलब्धि की दी।

प्रधानमंत्री प्रसाद बीमा योजना के अंतर्गत नागरिकों को विविध कार्यक्रमों के लिए उपलब्धि की दी।

प्रधानमंत्री प्रसाद बीमा योजना के अंतर्गत नागरिकों को विविध कार्यक्रमों के लिए उपलब्धि की